www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 159 | जौनपुर शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' अभियान जन आंदोलन बना : रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' अभियान के 11 वर्ष भारत की सामाजिक चेतना में आए सकारात्मक परिवर्तन के सशक्त प्रतीक हैं। यह अभियान आज एक सरकारी योजना से आगे बढ़कर जन–आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। इसने सामाजिक दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन लाते हुए बेटियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए हैं। मुख्यमंत्री ने एक्स पर गुरुवार को पोस्ट करते हुए कि हमारी बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा रही हैं। वे खेल के मैदानों में पदक जीत रही हैं, विज्ञान और तकनीक में नवाचार कर रही हैं, कॉर्पोरेट जगत में नेतृत्व कर रही हैं और सीमाओं पर देश की रक्षा में तैनात हैं। शिक्षा से लेकर उद्यमिता तक बेटियों की बढ़ती भागीदारी नए भारत की वास्तविक शक्ति है।उन्होंने नारी शक्ति के सशक्तीकरण और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रधानमंत्री का हृदय से आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि बेटियों की यही सफलता और स्वावलंबन विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेगा। उल्लेखनीय है कि 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के घटते लिंगानुपात की समस्या को दूर करना, उन्हें शिक्षित करना और सशक्त बनाना है।

बिहार के सीवान में मुख्यमंत्री नीतीश के आगमन के बीच धमाका

पटना, (एजेंसी)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर गुरुवार को सिवान पहुंचे। इस बीच मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल से कुछ दूरी पर धमाके से हड़कंप मच गया। यह धमाका हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बड़रम गांव में हुआ है। शुरुआती जांच में पता चला है कि विस्फोट पटाखों के कारण हुआ है, जिसमें एक युवक की मौत की सूचना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़रम गांव में अवैध रूप से पटाखा या विस्फोटक सामग्री बनायी जा रही थी। इसी दौरान अचानक जोरदार धमाका हुआ है। इस धमाके की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई है। आस–पास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज दूर तक सुनायी दी। धमाके की आवाज सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। हुसैनगंज थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और इलाके को चारों तरफ से घेरकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मलबे को हटाने में जुटी है। साथ ही यह पता लगाने में जुटी है कि यह धमाका किस तरह का था और इसमें और कितने लोग शामिल थे। मामले की सूचना फॉरेंसिक टीम को भी दे दी गई है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

विधायिका ही न्याय, समता और संप्रभुता का आधार : सीएम योगी

लखनऊ, (संवाददाता)। लोकतंत्र की आत्मा विधायिका में निहित है और यहीं से न्याय, समता व संप्रभुता का मार्ग तय होता है। 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात कहते हुए सम्मेलन को लोकतांत्रिक संस्थाओं को नई दिशा देने वाला बताया। तीन दिन तक चले इस सम्मेलन में देशभर से आए पीठासीन अधिकारियों के अनुभव, संवाद और मंथन के बाद 'विकसित भारत–2047' के लक्ष्य को लेकर छह महत्वपूर्ण संकल्प पारित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के माध्यम से पिछले तीन दिनों में देशभर से आए पीठासीन अधिकारियों, विधायी कार्यों से जुड़े अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस आयोजन ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को नई ऊंचाई देने का कार्य किया है। वास्तव में न्याय कैसे प्राप्त होगा, यह विधायिका के माध्यम से ही तय होता है। सरकार की योजनाएं कैसे क्षमता–आधारित समाज के निर्माण में योगदान दें, इसका मंच भी विधायिका ही है। संप्रभुता का सशक्त उदाहरण विधायिका प्रस्तुत करती है, जहां सहमति और असहमति के बीच सार्थक संवाद देखने को मिलता है। यह भारत का सौभाग्य है कि यहां लोकतंत्र की सर्वोच्च व्यवस्था लागू है। इस आयोजन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोग अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, वहीं मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश सहित देश के नागरिकों को भी इन गतिविधियों को जानने–सुनने का अवसर मिला है। उन्होंने सभी पीठासीन अधिकारियों, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति और आयोजन को सफल बनाने वाले अधिकारियों का उत्तर प्रदेश की ओर से हार्दिक अभिनंदन किया। सीएम योगी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री बार–बार लोकतंत्र की जननी बताते हैं। भले ही त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था औपचारिक रूप से बाद में लागू हुई हो, लेकिन गांवों में पंच–परंपरा सदियों पुरानी रही है। देश में भले ही रंग, रूप, खानपान और वेशभूषा अलग–अलग हों, लेकिन उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भारत एक भाव और एक आस्था से जुड़ा है। मुख्यमंत्री ने अपने संसदीय अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्हें पांच बार लोकसभा जाने का अवसर मिला, जहां से उन्होंने सीखा कि नियमों और परंपराओं के अंतर्गत सदन संचालन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि संसद के मॉडल को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल में सुधार किया गया, जिससे अब 20 प्रश्नों पर 20 सदस्य अपनी बात रख पा रहे हैं, जबकि पहले केवल दो–तीन सदस्य ही बोल पाते थे। सीएम योगी ने कहा कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की आवाज भी विधायिका में उसके प्रतिनिधित्व के माध्यम से सुनी जाती है। उन्हें प्रसन्नता है कि इस सम्मेलन में भी 'विकसित भारत' के लक्ष्य को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में 'विकसित भारत–विकसित उत्तर प्रदेश' पर हुई बहस में 377 विधायकों ने भाग लिया और रात भर सदन में उपस्थित रहकर अपने सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि इस विजन डॉक्यूमेंट की तैयारी में 500 जनप्रतिनिधियों के साथ–साथ 500 से अधिक बुद्धिजीवियों– सेवानिवृत्त मुख्य सचिव, कुलपति, शिक्षाविद,

वैज्ञानिक और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को जोड़ा गया। इन्हें 75 जिलों में जाकर समाज के हर वर्ग से संवाद करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके परिणामस्वरूप 98 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए, जिन्हें आईआईटी कानपुर के सहयोग से अंतिम रूप देकर विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में पेपरलेस बजट और पूरी तरह डिजिटल प्रणाली लागू की जा चुकी है,।

समृद्ध तमिलनाडु के लिए मजबूत राजग आवश्यक : अमित शाह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि टी.टी.वी. दिनाकरन के नेतृत्व वाली एएमएमके की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में वापसी से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गठबंधन और मजबूत हुआ है। शाह ने कहा कि तमिलनाडु के लोग आगामी विधानसभा चुनावों में राजग को

आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं ताकि राज्य को विकास और समृद्धि की नयी ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। तमिलनाडु के बहुप्रतीक्षित विधानसभा चुनावों से पहले, एएमएमके ने अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए राजग में वापसी की है। शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''समृद्ध तमिलनाडु के लिए मजबूत राजग। मैं टीटीवी दिनाकरन जी के नेतृत्व वाली अम्मा मक्कल मुनेत्र कषगम (एएमएमके) का राजग का हिस्सा बनने पर स्वागत करता हूं। तमिलनाडु के लोग द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के भ्रष्ट और वंशवादी शासन से तंग आ चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार को तमिलनाडु को विकास और समृद्धि की नयी ऊंचाइयों पर ले जाने का आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं।'' तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले टीटीवी दिनाकरन के नेतृत्व वाली एएमएमके बुधवार को फिर से राजग में शामिल हो गई।

हर क्षेत्र में बेटियां बना रही हैं नए रिकॉर्ड : पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्र सरकार के बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान ने गुरुवार को 11 साल पूरे किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि आज भारत की बेटियां हर क्षेत्र में नए रिकॉर्ड बना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म श्एक्सश पर लिखा, ष्कन्या को लक्ष्मी मानने वाले हमारे देश में 11 साल पहले आज ही के दिन बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी। यह बड़े गर्व की बात है कि आज भारत की बेटियां हर क्षेत्र में नित–नए रिकॉर्ड बना रही हैं।पीएम मोदी ने एक सुभाषित शेयर करते हुए लिखा गौरतलब है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई। इसका उद्देश्य महिला–पुरुष

के आधार पर चयन को रोकना, बालिकाओं के अस्तित्व व सुरक्षा को सुनिश्चित करना और बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह केंद्र सरकार की शत–प्रतिशत वित्तपोषित योजना है और इसे देश के सभी जिलों में चलाया जा रहा है।श्बेटी बचाओ–बेटी पढाओश अभियान ने पिछले वर्षों में सफलतापूर्वक राष्ट्रीय चेतना में जगह बनाई। इस अभियान ने समुदायों, सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज और मीडिया को लड़कियों के हक में सहायक और न्यायसंगत वातावरण को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम करने के लिए संगठित किया। इस कार्यक्रम ने जन्म के समय महिला–पुरुष अनुपात (एसआरबी) में सुधार, बालिका शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लड़कियों तथा महिलाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रगति भी हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के श्एचआईएम आईएसश के आंकड़ों के अनुसार, देश में जन्म के समय लिंगानुपात साल 2014–15 में 918 था, जो 2024–25 में बढ़कर 929 तक पहुंचा। वहीं, शिक्षा मंत्रालय के यूडीआईएसई के आंकड़ों के मुताबिक, माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात 75.51 प्रतिशत से बढ़कर 78 प्रतिशत तक पहुंचा है।

2047 के विकसित भारत का लक्ष्य मिलकर करना होगा पूरा : केशव मौर्य

आजमगढ, (संवाददाता)। स्वदेशी, विकास और विरासत के मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को आजमगढ़ की धरती से बड़ा संदेश दिया। जनपद दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम का पुलिस लाइन में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वे नगर के हरिऔध कला भवन पहुंचे, जहां आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में शिरकत कर उन्होंने सरकार की उपलब्धियों के साथ 2047 के विकसित भारत का विजन साझा किया। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार को नगर के हरिऔध कला केंद्र में आयोजित ब्रह्मर्षि स्वामी सहजानंद सेवा न्यास

एवं महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में उन्होंने शिरकत की और कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में स्वदेशी की सोच बदली है। पहले स्वदेशी की बात करने में लोगों को संकोच होता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वदेशी पर गर्व किया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि देशवासी स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करें तो दुनिया की कोई ताकत भारत को पीछे नहीं रख सकती। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार ने गरीबों के खिलाफ जंग जीतते हुए 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की स्थापना इसका बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बन चुका है, जहां हर मंडल में कम से कम एक विश्वविद्यालय और हर जनपद में मेडिकल कॉलेज की दिशा में ठोस काम हुआ है। उन्होंने 'एक जनपद, एक उत्पाद' योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे प्रदेश में आर्थिक क्रांति आई है, लेकिन लक्ष्य यहीं तक सीमित नहीं है। गांवों के विकास से ही शहर, जनपद और प्रदेश का विकास संभव है।

दुनिया भारत को बेंगलुरु के नजरिए से देखती है : डी के शिवकुमार

कर्नाटक, (एजेंसी)। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने वैश्विक निवेशकों के बीच देश के शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में कर्नाटक की वकालत करते हुए बुधवार को कहा कि दुनिया भारत को बेंगलुरु के नजरिए से देखती है। शिवकुमार ने स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक के दौरान यहां पीटीआई– से कहा कि दावोस में सीखने के लिए बहुत कुछ है और वह दुनिया भर के विभिन्न नेताओं से मिले हैं, और वह यह महसूस करते हैं कि भारत को बेंगलुरु के माध्यम से देखा जाता है। उन्होंने कहा, '' दुनिया के नेता यही कहते हैं। और मैं उन्हें कर्नाटक का महत्व बता रहा हूं और यह बता रहा हूं कि यह काम करने के लिए एक बेहतरीन राज्य है। '' यहां पहली बार आए

शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक उद्योग जगत के सभी वर्गों के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान करता है। शिवकुमार ने कहा कि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में कई अवसर हैं। उन्होंने कहा, ''वैश्विक निवेशक पूरे राज्य में आवागमन को लेकर हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों पर नजर रख रहे हैं और वे दो–स्तरीय और तीन–स्तरीय शहरों में किए जा रहे कार्यों में भी रुचि रखते हैं।'' कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने कहा, '' बेंगलुरु में हम मेट्रो, फ्लाईओवर, पास, सुरंगों और कई अन्य चीजों पर भारी निवेश कर रहे हैं। सभी का मानना है कि बेंगलुरु बहुत सुरक्षित है, यहां प्रदूषण नहीं है और मौसम और संस्कृति भी शानदार हैं।

राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बीच में छोड़ा अभिभाषण, सदन से किया वॉकआउट

कर्नाटक, (एजेंसी)। कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने गुरुवार को राज्य सरकार के असेंबली में दिए जाने वाले पारंपरिक भाषण के कुछ हिस्सों को पढ़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने प्रस्तावित बिल को लागू करने से जुड़े हिस्सों पर आपत्ति जताई और सदन से बाहर चले गए। यह राजभवन और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के बीच एक नया राजनीतिक टकराव है। यह घटना बजट सत्र की शुरुआत में हुई, जब गवर्नर को सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं को बताते हुए भाषण देना था। गहलोत ने योजना में बदलाव लाने

वाले विवादास्पद कानून से जुड़े कुछ खास पैराग्राफ पर आपत्ति जताई, और कहा कि यह भाषण सरकारी प्रोपेगेंडा जैसा है। गवर्नर का यह कदम तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि के राज्य असेंबली में भाषण दिए बिना बाहर चले जाने के एक दिन बाद आया है, जिन्होंने टेक्स्ट में ष्गलतियोंष का हवाला दिया था। केरल में भी, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कथित तौर पर अपने भाषण के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया था, और राजभवन ने दावा किया कि उनके सुझाए गए बदलावों को ड्राफ्ट में शामिल नहीं किया गया था। यह घटना राजभवन और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बीच चल रहे लंबे शीतयुद्ध का ताजा अध्याय है। इससे पहले भी मुडा घोटाले और अन्य प्रशासनिक नियुक्तियों को लेकर राज्यपाल और सरकार के बीच तीखी बयानबाजी हो चुकी है। कांग्रेस सरकार ने राज्यपाल पर केंद्र के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है।

अमित मालवीय पर हुआ था झूठा केस, सत्य की हमेशा जीत होती है : शहजाद पूनावाला

नई दिल्ली, (एजेंसी)। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एक पोस्ट को लेकर भाजपा नेता अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर रद्द करने के मद्रास हाई कोर्ट के फैसले का भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। नई दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय में बुधवार को प्रेस वार्ता कर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, ष्मंगलवार को मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के बारे में एक बात जरूर कहनी चाहिए। सत्यमेव जयते दृ सत्य की हमेशा जीत होती है। मद्रास हाई कोर्ट ने उस एफआईआर को रद्द कर दिया है जो बदले की भावना से सिर्फ हमारे आईटी सेल प्रमुख और बंगाल के सह–प्रभारी अमित मालवीय को सच बोलने के लिए सजा देने और दंडित करने के मकसद से दायर की गई थी। उन्होंने कहा कि 2023 में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु में एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने न सिर्फ सनातन धर्म का विरोध किया, बल्कि उसे पूरी तरह खत्म करने की बात कही थी। उन्होंने सनातन की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी। एक तरह से, यह हिंदुओं के नरसंहार की एक डरावनी पुकार थी। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, पूरी डीएमके और राज्य सरकार की मशीनरी अमित मालवीय के पीछे पड़ गई, जिन्होंने सिर्फ यह मुद्दा उठाया था। शहजाद पूनावाला ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर रद्द कर दी और डीएमके के बयान को हेट स्पीच के बराबर बताया। कोर्ट ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ दायर की गई एफआईआर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग थी। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस–डीएमके इकोसिस्टम से पूछना चाहता हूं, अमित मालवीय के मामले में बोलने की आजादी का क्या हुआ? आपने सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए एक झूठा केस किया और आप अपने राजनीतिक विरोधी के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब एक डीएमके नेता खुलेआम कहता है कि हिंदुओं को खत्म कर देना चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी चुप क्यों हैं? राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन को तुरंत उनके पद से हटा देना चाहिए और उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस देश की 80 प्रतिशत आबादी, हिंदू समुदाय के खिलाफ नफरत भरी बातें कही हैं, जिसे सही ही हेट स्पीच कहा जा रहा है। डीएमके भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक मानी जाने वाली सरकार चला रही है। उन्होंने कहा कि यहां तक घ्धकि तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी के ऊपर दीपस्तंभ पर पवित्र कार्तिगई दीपम जलाने के मामले में भी, डीएमके ने तमिलनाडु के जज जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया।

संपादकीय

विश्वास का संकट पैदा

पीएसएलवी के जरिए भारत ने उपग्रहों को धरती की कक्षा में स्थापित करने के कारोबार में अग्रणी देश बनने की महत्त्वाकांक्षा पाली है। मगर लगातार दो नाकामियों के बाद इस परियोजना को लेकर विश्वास का संकट पैदा हो गया है। पीएसएलवी रॉकेट की 62वीं उड़ान की नाकामी से भारत की उपग्रह संबंधी महत्त्वाकांक्षा को गहरा झटका लगा है। ये चोट इसलिए अधिक गंभीर है, क्योंकि पिछले साल मई में पीएसएलवी की 61वीं उड़ान भी फेल हो गई थी। सोमवार को पीएसएलवी–सी62 एक साथ 16 उपग्रहों को लेकर उड़ा, लेकिन उड़ान के तीसरे चरण में उससे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का संपर्क टूट गया। वे उपग्रह कहां गए, सोमवार को यह भी पता नहीं चल सका था। पीएसएलवी–सी61–ईओएस–09 के साथ भी ठीक यही हुआ था। यानी इसरो के वैज्ञानिक सात महीनों के दौरान उस खामी से निजात नहीं पा सके, जिस कारण बीते मई में उनका मिशन विफल हुआ। उस नाकामी की जांच के लिए समिति बनी थी, जिसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई, जहां उसे गोपनीय श्रेणी में डाल कर रखा गया है। यानी जिन करदाताओं के पैसे से इसरो चलता है, उन्हें इस सूचना से वंचित रखा गया है कि उनका पैसा क्यों बर्बाद हुआ। अब फिर वैसा ही हादसा ज्यादा बड़े पैमाने पर हुआ है। पीएसएलवी के जरिए भारत ने उपग्रहों को धरती की कक्षा में स्थापित करने के कारोबार में अग्रणी देश बनने की महत्त्वाकांक्षा पाली है। मगर अब आशंका है कि लगातार दो नाकामियों के बाद इस रॉकेट लॉन्च के लिए बीमा की रकम बढ़ जाएगी और जो देश या कंपनियां इसके जरिए अपने उपग्रह भेजना चाहेंगी, उनके लिए इसरो को ठेका देना बेहद महंगा हो जाएगा। विश्वास का जो संकट पैदा हुआ है, वह इसके अलग है। इस विकट स्थिति से निकलने का उचित तरीका यही होगा कि भारत सरकार और इसरो पूरी पारदर्शिता बरतें। वे दोनों नाकामियों के बारे में सभी हित–धारकों को भरोसे में लें। नाकामियों के लिए जवाबदेही तय करना भी जरूरी है। आखिर बिना पुरानी खामी को दूर किए अगले लॉन्च को कैसे हरी झंडी दी गई और किस स्तर पर ये फैसला हुआ, यह देश को मालूम होना चाहिए। पीएसएलवी–सी62 डीआरडीओ का अन्वेष उपग्रह भी ले जा रहा था। यानी इस नाकामी का असर भारत की रक्षा तैयारियों पर भी पड़ेगा। इसलिए इस संबंध में पूरी जांच एवं पारदर्शिता अनिवार्य है।

शांति का मुखौटा, सत्ता की रणनीतिः ट्रंप का वैश्विक विरोधाभास

ललित

नोबेल शांति पुरस्कार की उत्कट अभिलाषा में डूबे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का व्यक्तित्व और कार्यशैली वैश्विक राजनीति के लिए एक गहरी विडंबना एवं विरोधाभास बनकर उभरी है। शांति का मसीहा बनने का उनका दावा जितना आकर्षक दिखता है, उतना ही विरोधाभासी उनके कदमों का यथार्थ है। दुनिया के अलग–अलग हिस्सों में वे जहां शांति स्थापित करने का श्रेय लेना चाहते हैं, वहीं उनके निर्णय, वक्तव्य और नीतियां अक्सर युद्ध, अशांति, भय और अस्थिरता को जन्म देती दिखाई देती हैं। यह कैसी शांति है, जो बमों की गूंज, प्रतिबंधों की मार और नफरत की भाषा के साथ चलती है? यह कैसा शांति–दूत होने का नाटक है, जिसमें मानवता का रक्त बहता रहे और सत्ता अपने हित साधती रहे? गाजा में शांति स्थापना के लिए ट्रंप की प्रस्तावित योजना इसी विरोधाभास का नवीन उदाहरण है। इसे शांति से अधिक व्यापारिक सौदे की तरह प्रस्तुत किया गया, मानो दशकों से हिंसा, विस्थापन और अस्मिता के संकट से जूझ रहे लोगों का भविष्य किसी रियल एस्टेट या आर्थिक पैकेज से तय किया जा सकता हो। अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, स्थानीय जनता की सहमति और जवाबदेही–इन सबको दरकिनार कर शांति थोपने की यह कोशिश बताती है कि ट्रंप की दृष्टि में शांति कोई नैतिक या मानवीय मूल्य नहीं, बल्कि शक्ति–प्रदर्शन और राजनीतिक लाभ का औजार है। इस तरह बमों के साये में शांति का दावा डकोसला ही है, जिसमें शांति का सौदा एवं सत्ता की भूख ही दिखती है। ट्रंप की कथित शांति योजना, शांति के नाम पर वर्चस्व की राजनीति ही है। ऐसा लगता है शब्द अहिंसा के और कर्म हिंसा के है। ट्रंप संयुक्त राष्ट्र को अक्षम, पक्षपाती और नौकरशाही से ग्रस्त बताकर उसकी अवहेलना करते रहे हैं, जबकि सच यह है कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं का ढांचा अनिवार्य है। शक्तिशाली देशों को जब यह ढांचा अपने अनुकूल नहीं लगता, तो वे उसे कमजोर करने लगते हैं–ट्रंप इसी प्रवृत्ति का मुखर चेहरा हैं। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित नए वैश्विक शांति संस्थान का विचार अपने आप में जितना आकर्षक शब्दों से सुसज्जित है, उतना ही अपने अंतर्विरोधों में उलझा हुआ भी है। शांति स्थापना के नाम पर एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था खड़ी करने की कोशिश, जो संयुक्त राष्ट्र जैसे स्वीकृत बहुपक्षीय ढांचे को दरकिनार करती हो, वस्तुतः शांति से अधिक सत्ता–केंद्रित वर्चस्व की आकांक्षा को उजागर करती है। यह प्रश्न स्वाभाविक है कि जिस नेतृत्व की नीतियों का आधार हथियारों के निर्माण और बिक्री, सैन्य गठबंधनों के विस्तार, युद्ध की धमकियों और आर्थिक दंड के जरिये दुनिया पर दबाव बनाना रहा हो, वह अचानक शांति का नया ठेकेदार कैसे बन सकता है? ट्रंप की राजनीतिक सोच में शांति किसी मानवीय प्रतिबद्धता का नहीं, बल्कि सौदेबाजी, नियंत्रण और लाभ का साधन प्रतीत होती है। इसलिए उनके प्रस्तावित शांति संस्थान की उपयोगिता पर गंभीर संदेह खड़ा होता है। बिना वैधता, जवाबदेही और वैश्विक सहमति के खड़ी की गई कोई भी संस्था शांति का वाहक नहीं बन सकतीय वह केवल शक्तिशाली देशों की इच्छाओं को थोपने का उपकरण या जरिया ही बनती है। इस संदर्भ में ट्रंप का यह प्रयास शांति की दिशा में एक ठोस पहल नहीं, बल्कि हिंसा–प्रधान नीतियों पर पर्दा डालने और वैश्विक शासन व्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत करने का एक और षडयंत्र एवं कुचेष्टा ही दिखाई देता है। ट्रंप की सोच में शांति का अर्थ संघर्षों का समाधान नहीं, बल्कि उन्हें अपने पक्ष में मोड़ना है। कभी वे संयुक्त राष्ट्र के समानांतर इस तरह की एक कथित शांति–व्यवस्था खड़ी करने की बात करते हैं, तो कभी ईरान पर युद्ध की धमकी देते हैं। एक ओर वे यूरोपीय देशों की तारीफ कर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करते हैं, दूसरी ओर उन्हीं देशों पर व्यापारिक प्रतिबंधों और सैन्य खर्च का दबाव डालते हैं। यह दोहरा आचरण और कथनी और करनी का भेद वैश्विक अस्थिरता को बढ़ाता है। शांति की भाषा बोलते हुए हथियारों की बिक्री, सैन्य गठबंधनों का विस्तार और आर्थिक दंड–ये सब उनकी नीतियों के अभिन्न अंग रहे हैं। परिणामस्वरूप दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां युद्ध की आहटें तेज हैं और मानवता अस्तित्व के मुहाने पर पहुंचती प्रतीत होती है। गाजा संकट के संदर्भ में यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि बिना वैधता, सहमति और जवाबदेही के थोपी गई शांति कभी स्थायी नहीं होती। यदि नागरिकों की सुरक्षा, जीवन की गरिमा और राजनीतिक अधिकारों को नजरअंदाज किया जाए, तो कोई भी समझौता खोखला साबित होगा। ट्रंप का दृष्टिकोण इन मूलभूत सच्चाइयों को अक्सर अनदेखा करता है। आर्थिक वादों को राजनीतिक अधिकारों के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना एक खतरनाक भ्रम है, जो जमीनी वास्तविकताओं के बोझ से ढह जाता है। शांति तभी टिकाऊ हो सकती है जब उसमें स्थानीय लोगों की वास्तविक आवाज शामिल हो, उनके दुख–दर्द को समझा जाए और न्यायपूर्ण समाधान की दिशा में ईमानदार पहल हो। भारत को गाजा में शांति प्रयासों में शामिल करने का प्रस्ताव भी इसी जटिलता को उजागर करता है। भारत का कूटनीतिक इतिहास बहुपक्षवाद, संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका और द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थन से जुड़ा रहा है। भारत के इस्राइल से अच्छे संबंध हैं, तो अरब देशों में भी उसकी विश्वसनीयता बनी हुई है। लेकिन यदि शांति प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र को दरकिनार करती है, तो यह भारत की स्थापित कूटनीतिक परंपरा के अनुकूल नहीं होगा। भारत ने हमेशा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बजाय स्थिरता और संवाद को प्राथमिकता दी है। ऐसे में ट्रंप–प्रेरित पहल में शामिल होना भारत के लिए भी एक नैतिक और रणनीतिक चुनौती बन सकता है। वास्तव में ट्रंप की नीतियां एक ऐसे विश्व–दृष्टिकोण को

प्रतिबिंबित करती हैं, जहां शक्ति ही सत्य है और नैतिकता केवल भाषणों तक सीमित है। उनकी बयानबाजी में नफरत और विभाजन की छाया साफ दिखती है। आप्रवासन, नस्ल, धर्म और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर उनकी भाषा ने वैश्विक स्तर पर असहिष्णुता को बढ़ावा दिया। जब विश्व का सबसे शक्तिशाली देश इस तरह का संदेश देता है, तो उसका असर सीमाओं से परे जाता है। युद्ध केवल गोलियों और मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता, वह विचारों और शब्दों से भी लड़ा जाता हैकृऔर ट्रंप के शब्द अक्सर आग में घी डालने का काम करते रहे हैं। आज दुनिया जिन संकटों से जूझ रही है–यूक्रेन से लेकर मध्य पूर्व तक, एशिया से अफ्रीका तक, उनमें कहीं–न–कहीं महाशक्तियों की स्वार्थपूर्ण नीतियों की छाया है। ट्रंप का दौर इस प्रवृत्ति को और उग्र बनाता दिखाई दिया, जहां वैश्विक सहयोग के बजाय 'मैं पहले' की मानसिकता हावी रही। शांति के नाम पर दबाव, सौदेबाजी और धमकी–यह त्रयी मानवता के लिए घातक है। जो नेता स्वयं को शांति का प्रतीक बताता है, उससे अपेक्षा होती है कि वह पुल बनाए, दीवारें नहींय संवाद बढ़ाए, युद्ध नहींय भरोसा पैदा करे, भय नहीं। इस तरह प्रश्न यही है कि क्या शांति पुरस्कार की आकांक्षा मात्र से कोई शांति–दूत बन सकता है? यदि जवाबदेही, सहमति और मानवीय मूल्यों के बिना शांति थोपने की कोशिश की जाए, तो वह शांति नहीं, एक नया संघर्ष जन्म देती है। ट्रंप की कार्यशैली इसी सच्चाई की गवाही देती है। आज जब मानवता युद्धों में अपने जीवन को खो रही है, तब शांति का ढोंग और भी क्रूर प्रतीत होता है। दुनिया को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो शक्ति के प्रदर्शन से नहीं, बल्कि करुणा, न्याय और बहुपक्षीय सहयोग से शांति की राह प्रशस्त करे। अन्यथा शांति मसीहा होने का यह नाटक इतिहास में एक विफल और खतरनाक प्रयोग के रूप में ही दर्ज होगा।

एआई से आत्मनिर्भरता तक : महिलाओं और युवाओं का नया भविष्य

श्रीमती कविता भाटिया

भारत इंडिया–एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की तैयारियों में जुटा है। इस समिट में दुनिया भर के एआई के धुरंधर शामिल होंगे और इस वैश्विक मंच पर भारत के युवाओं को भी अपना पुरुषार्थ दिखाने का अवसर मिलेगा। अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल मशीनों, एल्गोरिदम या ऑटोमेशन तक सीमित नहीं है। असली चर्चा इस बात की है कि एआई को सभी के लिए उपयोगी और सुलभ कैसे बनाया जाए। खासतौर पर महिलाओं, युवाओं और उन कामगारों के लिए, जो अब तक औपचारिक अर्थव्यवस्था से दूर रहे हैं। एआई की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि वह इंसानों की जगह ले ले, बल्कि यह है कि वह इंसानों की क्षमता बढ़ाए। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो एआई महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकता है, युवाओं को नए कौशल दे सकता है और असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को सुरक्षा और अवसर दोनों दे सकता है। इसी सोच के साथ मार्च 2024 में सरकार ने इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी। इस मिशन का उद्देश्य हैकृ भारत में एआई का विकास करना और एआई को भारत की जरूरतों के अनुसार काम में लाना। इसके तहत कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाने, नए इनोवेशन सेंटर खोलने, भरोसेमंद डेटा प्लेटफॉर्म बनाने, एआई आधारित एप्लिकेशन विकसित करने, युवाओं को भविष्य के कौशल सिखाने और स्टार्टअप्स को वित्तीय मदद देने जैसे कई कदम उठाए गए। उनके सकारात्मक और सुखद परिणाम अब शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, लैब से लेकर खेतों तक और संगीत व कला जैसे हर क्षेत्र में दिखाई देने लगे हैं। इस मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर, जहाँ खास तौर पर समावेशी विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ ऐसे एआई मॉडल तैयार किए जा रहे हैं, जो भारत की भाषाई और सामाजिक विविधता को समझ सकें। ये मॉडल किसानों, महिला उद्यमियों, गिग वर्कर्स और छोटे व्यापारियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में काम करने वाले एआई सहायक, छोटे–छोटे सलाह देने वाले डिजिटल टूल और अलग–अलग क्षेत्रों के लिए ज्ञान आधारित सिस्टम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। एआई समिट से निकलेगी राह दुनिया के कई देशों में एआई को केवल उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के औजार के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन भारत में एआई का असली असर रोजगार, सुरक्षा, प्रशिक्षण और अवसर के रूप में सामने आ रहा है। फरवरी 2026 में होने वाले इंडिया–एआई इम्पैक्ट समिट में इसी सोच पर चर्चा होगी कि एआई का इस्तेमाल जनता, विकास और धरती के हित में कैसे किया जाए। आज भारत की गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में महिलाएं एआई की मदद से नई पहचान बना रही हैं। कई महिला उद्यमी एआई आधारित ऑनलाइन बाजारों से जुड़कर अपना कारोबार बढ़ा रही हैं। वहीं, टैक्सी चलाने वाली या डिलीवरी का काम करने वाली महिलाएं एआई आधारित सुरक्षा सुविधाओं की वजह से ज़्यादा सुरक्षित और आत्मविश्वास से भरी महसूस कर रही हैं। उदाहरण के लिए, ब्यूटी और हेल्थ से जुड़े प्लेटफॉर्म एआई का इस्तेमाल कर ग्राहकों को सही सेवा प्रदाता से जोड़ते हैं। इसमें स्थान, कौशल और पुराने अनुभव जैसी जानकारियों का ध्यान रखा जाता है। इससे महिलाओं को लचीले काम के घंटे, तय आमदनी और बेहतर सुरक्षा मिलती है। इसी तरह, टैक्सी और डिलीवरी सेवाओं में रियल–टाइम लोकेशन शेयरिंग और वॉयस–एक्टिवेटेड इमरजेंसी फीचर जैसी सुविधाओं ने महिला ड्राइवर्स का भरोसा बढ़ाया है। ग्रामीण और अर्ध–शहरी भारत में भी एआई डिजिटल समावेशन को आगे बढ़ा रहा है। क्षेत्रीय भाषाओं में काम करने वाले एआई सहायक और आवाज से चलने वाली डिजिटल भुगतान सेवाएं उन महिलाओं के लिए मददगार साबित हो रही हैं, जो पढ़ना–लिखना कम जानती हैं। अब वे बिना झिझक अपने पैसों का लेन–देन और प्रबंधन कर पा रही हैं। श्युवा एआई फॉर ऑलय युवाओं के लिए एआई केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि नए भविष्य का दरवाजा है। सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर देशभर में एआई से जुड़े कौशल सिखा रहे हैं, चाहे वह बुनियादी डिजिटल जानकारी हो या उन्नत मशीन लर्निंग। इसी कड़ी में शुरू किया गया श्युवा एआई फॉर ऑलय अभियान लाखों छात्रों को एआई की बुनियादी समझ दे रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिये यह कोशिश की जा रही है।

पहले दिन ही ताबड़तोड़ ऐलान कर नितिन नवीन ने अपने इरादे बता दिए

संतोष

देश की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को अब तक का अपना सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन (45 वर्ष) के रूप में मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा समेत कई अन्य दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में नितिन नवीन ने मंगलवार, 20 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने सबसे बड़ी या यूं कहें कि सबसे पहली चुनौती आगामी विधानसभा चुनाव है। क्योंकि पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही नवीन के पास होने या फेल होने की चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। दक्षिण भारत के राज्यों में पार्टी का जनाधार बढ़ाना और कर्नाटक में पार्टी को फिर से सत्ता में लाना भी उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। यह चुनौती उनके पहले दिन के फैसलों में भी साफ–साफ नजर आती है। पार्टी अध्यक्ष का कार्यभार संभालते ही उन्होंने पहले दिन ही ताबड़तोड़ अंदाज में केरल, तेलंगाना, बेंगलुरु और चंडीगढ़ के लिए चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारियों की नियुक्तियों कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। पहले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को क्यों अपना बॉस बताया था, यह कुछ घंटे बाद ही साफ हो गया क्योंकि जिन नेताओं को नितिन नवीन के आदेश से नई जिम्मेदारी दी गई है,उसमें कई नाम बहुत ही चौंकाने वाले हैं। नवीन ने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल के पहले ही दिन, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को केरल विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त करने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही तावड़े को चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया गया है। तावड़े बिहार के प्रभारी भी हैं। तावड़े के साथ ही केरल में चुनाव के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। शोभा करंदलाजे कर्नाटक से सांसद हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर जेपी नड्डा तक, केरल हमेशा से ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। नवीन पहले दिन से ही इस अभियान में जुट गए हैं। दक्षिण भारत में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की चुनौती में कर्नाटक भी शामिल हैं। कर्नाटक दक्षिण भारत का वह राज्य है, जहां सबसे पहले कमल खिला था लेकिन आज वहां कांग्रेस की सरकार है। शायद यही एक बड़ी वजह है कि एक चौंकाने वाला फैसला करते हुए राम माधव जैसे दिग्गज नेता को ग्रेटर बेंगलुरु निगम चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी बनाया गया है।राम माधव अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। राम माधव के साथ ही राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और महाराष्ट्र के विधायक संजय उपाध्याय को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। तेलंगाना में होने वाले नगर निगम चुनावों को भी पूरी गंभीरता से लेते हुए नितिन नवीन ने पहले ही दिन तीन बड़े नेताओं को वहां की जिम्मेदारी थमा दी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार को वहां का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। शेलार नितिन नवीन के साथ काम कर चुके हैं, महाराष्ट्र युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह

चुके हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के काफी करीबी माने जाते हैं। उनके साथ ही राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी एवं हरियाणा से राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों से यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि बतौर युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को कर्नाटक, तेलंगाना , केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम जैसे राज्यों में चुनावी जीत हासिल कर, अपनी क्षमता को साबित करना ही होगा।

राजनीतिक संकल्प को परखने के लिए फिर वापस आया क्रीमी लेयर का सवाल

के रवींद्रन

राजनीति क्रीमी लेयर की बहस एक बुनियादी सवाल उठाती है क्या आरक्षण नीति को ग्रुप आधारित उपाय के तौर पर समय के साथ रोक देना चाहिए, या इसे बदलती सामाजिक सच्चाइयों के अनुरूप बदलना चाहिए? संवैधानिक न्यायशास्त्र बाद वाले की तरफ झुका है, इस बात पर जोर देते हुए कि सकारात्मक कार्रवाई लक्षित और समानुपातिक रहना चाहिए। क्रीमी लेयर की बहस फिर एक बार संवैधानिक और राजनीतिक ध्यान के केंद्र में वापस आ गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या पिछड़े वर्गों के अंदर आर्थिक और सामाजिक तरक्की की वजह से आरक्षण के फायदों तक पहुंच सीमित हो जायेगा? कोर्ट का यह नया सवाल, जो पहले के दो नोटिसों के बाद आया है, जिनका अब तक कोई जवाब नहीं मिला, ने सत्तारूढ़ राजनीतिज्ञों के अंदर एक ऐसे मुद्दे का सामना करने में लंबे समय से चली आ रही हिचकिचाहट को दिखाया है जो सामाजिक न्याय, चुनावी गणित और संवैधानिक नैतिकता के बीच जुड़ा है।इस मामले के केंद्र में वह तनाव है जो सकरात्मक कार्रवाई की नीति के शुरुआती सालों से मौजूद है। आरक्षण को ढांचागत और ऐतिहासिक रूप से अलग–थलग किए जाने को ठीक करने के लिए सोचा गया था, जिसका मकसद उन समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व पक्का करना था जिन्हें शिक्षा, रोजगार और सत्ता तक एक व्यवस्थित तरीके से पहुंच से दूर रखा गया था। लेकिन, दशकों से इस बात के सुबूत मिले हैं कि कुछ पिछड़े वर्गों में, एक छोटा लेकिन असरदार हिस्सा लगातार फायदों का ज़्यादा हिस्सा हासिल करता रहा है। इस घटना को कानूनी और नीतिगत बातचीत में श्क्रीमी लेयरश कहा जाता है, जिसने उस नैतिक साफ सोच को और मुश्किल बना दिया है जो कभी आरक्षण नीति का आधार थी।भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई फैसलों में इस चिंता को दूर किया है, खासकर अपने उन फैसलों में जिन्होंने केन्द्रीय नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया। इसका तर्क सीधा थारू आरक्षण उन लोगों के लिए होना चाहिए जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, न कि उनके लिए जो पहले ही आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक पूंजी की दहलीज पार कर चुके हैं। फिर भी, न्यायालय के दबाव के बावजूद, इसे लागू करना आधा–अधूरा और असमान रहा है, और राजनीतिक रूप से विवादित भी रहा है।इस मुद्दे का मौजूदा उभार लंबे समय से कार्यपालिका की चुप्पी के साथ न्यायालय की बेसब्री को दिखाता है। केंद्र सरकार से बार–बार अपना रुख साफ करने के लिए कहकर, न्यायालय यह संकेत दे रहा है कि टालमटोल अब एक मंजूर नीति नहीं है। पहले के नोटिसों पर कोई औपचारिक जवाब न मिलने से यह सोच और गहरी हुई है कि संवैधानिक सिद्धांतों के बजाय राजनीतिक सोच ही कार्रवाई न करने की वजह बन रही है। इस मुद्दे की संवेदनशीलता को नकारा नहीं जा सकता। पिछड़े वर्ग एक जैसे नहीं हैं, और उन्होंने जो ऐतिहासिक अन्याय झेला है, वह सदियों से अलग–थलग रहने, बदनामी और शोषण का नतीजा है। इन समुदायों में से कई लोगों के पास अभी भी अच्छी स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, जमीन का मालिकाना हक, और पक्की नौकरी तक पहुंच नहीं है। उनके लिए, आरक्षण एक खास अधिकार के बजाय एक जीवनरेखा बना हुआ है। योग्याता के मानदंड पर फिर से विचार करने की किसी भी कोशिश को मुश्किल से जीते गए अधिकारों पर हमले के तौर पर दिखाया जा सकता है, एक ऐसी कहानी जिसका सामना करने से राजनीतिज्ञ स्वाभाविक रूप से सावधान रहते हैं।साथ ही, पिछड़े वर्गों के अंदर अंदरूनी भेदभाव को नजरअंदाज करने से ऐसी गलतफहमियां पैदा हुई हैं जो सकारात्मक कार्रवाई के मकसद को ही कमजोर करती हैं। जिन परिवारों को पीढ़ियों से आरक्षण का फायदा मिला है, उन्हें अक्सर ऐसे फायदे होते हैं जो उन्हें उसी सामाजिक श्रेणी के सबसे गरीब और सबसे हाशिए पर पड़े लोगों से साफ तौर पर अलग करते हैं। शहरी नेटवर्क , उच्च शिक्षा, पेशेवर नौकरी और राजनीतिक असर तक पहुंच उन्हें बार–बार आरक्षित मौके पाने में मदद करती है, जिससे पहली पीढ़ी के उम्मीदवार बाहर हो जाते हैं। यह गत्यात्मकता न केवल पिछड़े वर्गों के अंदर गैर–बराबरी को बनाए रखता है, बल्कि उन लोगों में नाराजगी भी बढ़ाता है जिन्हें लगता है कि व्यवस्था ने उन्हें नाकाम कर दिया है।इसलिए क्रीमी लेयर की बहस एक बुनियादी सवाल उठाती हैरू क्या आरक्षण नीति को ग्रुप आधारित उपाय के तौर पर समय के साथ रोक देना चाहिए, या इसे बदलती सामाजिक सच्चाइयों के अनुरूप बदलना चाहिए? संवैधानिक न्यायशास्त्र बाद वाले की तरफ झुका है, इस बात पर जोर देते हुए कि सकारात्मक कार्रवाई लक्षित और समानुपातिक रहना चाहिए। न्यायालय का इस मुद्दे पर फिर से विचार करने पर जोर देना इस चिंता का संकेत देता है कि आरक्षण का असली कारण सुस्ती और राजनीतिक सावधानी से कमजोर हो रहा है।हालांकि, राजनीतिक हिचकिचाहट, पहले से बने वोट बैंक को अस्थिर करने के डर से जुड़ी है। पिछड़े वर्ग की राजनीति दशकों से राष्ट्रीय और राज्य चुनावों में एक अहम

ताकत रही है। आरक्षण के फायदों तक पहुंच को कम करने वाले किसी भी कदम से विरोध और चुनावी नतीजों का खतरा रहता है। इसने एक गलत प्रोत्साहन ढांचा बनाया है जहां एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने, विचारधारा की परवाह किए बिना, साफ–सफाई के बजाय भ्रांति को प्राथमिकता दी है। फिर भी, लगातार टालमटोल करने के अपने जोखिम हैं। जैसे–जैसे आरक्षण के फायदे एक छोटे से हिस्से तक तेजी से पहुंचते जा रहे हैं, नीति की न्यायसंगतता पर ही दबाव पड़ता जा रहा है। सकारात्मक कार्रवाई की आलोचना करने वाले अक्सर क्रीमी लेयर के कब्जे को इस बात का सुबूत बताते हैं कि आरक्षण नुकसान को ठीक करने के बजाय खास अधिकार को इनाम देता है। भरोसेमंद सुधार के बिना, ये आलोचनाएं जोर पकड़ती हैं, जिससे आरक्षण की जरूरत के बारे में समाज की आम सहमति कम हो सकती है। इसलिए, एक ज़्यादा बारीक नजरिया अपनाने की जरूरत है। क्रीमी लेयर को पहचानना वर्जन के ऐतिहासिक उत्पीड़न की सच्चाई को खत्म नहीं करताय बल्कि, यह उत्पीड़ित समूहों के भीतर नतीजों की विविधता को स्वीकार करता है। आर्थिक तरक्की, स्थिर पेशेवर रोजगार, और पीढ़ी–दर–पीढ़ी शैक्षिक गतिशीलता ऐसे संकेत हैं जो उचित रूप से सकारात्मक समर्थन की कम जरूरत का संकेत दे सकते हैं। चुनौती इन संकेतों को इस तरह से परिभाषित करने में है जो निष्पक्ष तथा पारदर्शी हो और आर्थिक बदलावों को दिखाने के लिए समय–समय पर उसे परिष्कृत किया जाए। इसमें एक नैतिक पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो लोग पहले ही काफी फायदा उठा चुके हैं, वे आरक्षण का फायदा उठाते रहते हैं, तो वे ऐसा अपने ही समुदाय के अन्य लोगों की कीमत पर करते हैं। यह अंदरूनी असमानता एकजुटता को कमजोर करती है और सामाजिक न्याय की नीतियों की मुक्ति दिलाने की क्षमता को कमजोर करती है। क्रीमी लेयर को बाहर करने से, विरोधाभासी रूप से, आरक्षण मजबूत हो सकता है, यह सुनिश्चित करके कि फायदे उन लोगों तक पहुंचें जिन्हें उनकी सबसे ज़्यादा जरूरत है।न्यायपालिका की नई भागीदारी यह बताती है कि इस मुद्दे को अनिश्चित काल के लिए टालना अब संभव नहीं है। हालांकि अदालतों को नीति–निर्माण में दखल देने से बचने के लिए सावधानी से कदम उठाना चाहिए, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने में उनकी भूमिका यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि सकारात्मक कार्रवाई अपने मूल उद्देश्यों के साथ बनी रहे। कार्यपालिका से एक स्पष्ट रुख अपनाने के लिए दबाव डालकर, अदालत प्रभावी रूप से पूछ रही है कि क्या राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक न्याय को बदलती सामाजिक वास्तविकताओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए तैयार है? आखिरकार, एक सैद्धांतिक स्थिति बताने की जिम्मेदारी राजनीतिक कार्यपालिका की है। क्रीमी लेयर की पहचान करने और उसे बाहर करने के लिए एक पारदर्शी ढांचा, मजबूत डेटा कलेक्शन और समय–समय पर समीक्षा के साथ, कई चिंताओं को दूर कर सकता है। उतना ही महत्वपूर्ण ईमानदार सार्वजनिक संचार है जो सुधार को अधिकारों को कमजोर करने के रूप में नहीं, बल्कि गहरे समावेशन के उद्देश्य से सुधार के रूप में पेश करता है।

गोवंश वध करने वालों से पुलिस की मुठभेड

लखनऊ, (संवाददाता)। बहराइच के जरवल रोड के ग्राम मुड़ियाडीह जंगल में बृहस्पतिवार तड़के गोवंश वध की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई, जबकि दो अन्य को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। पुलिस ने मौके से गोवंश के अवशेष, तमंचा, कारतूस, बांका और रस्सी बरामद की है। सुबह करीब 6रू40 बजे पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम मुड़ियाडीह थाना जरवल रोड के जंगल में कुछ लोग गोवंश का वध कर मांस लेकर बाहर निकलने वाले हैं। इस पर प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में एसएसआई बिंदेश्वरी यादव,

उपनिरीक्षक दिनेश कुशवाहा, आरक्षी शुभांशु, रामसागर, हेड कांस्टेबल रणजीत सिंह व आरक्षी राजीव यादव सहित पुलिस टीम जंगल मुड़ियाडीह पहुंची। पुलिस टीम को देखते ही तीन संदिग्ध कटे जानवर का मांस, बांका और रस्सी लेकर भागने लगे। पीछा करने पर आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान जाफर पुत्र मुश्ताक निवासी मुड़ियाडीह थाना जरवल रोड के रूप में हुई। घायल जाफर को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) जरवल भेजा गया है। वहीं मौके से दो अन्य आरोपियों हकीम पुत्र ताहिर निवासी मुड़ियाडीह तथा रिजवान पुत्र सैयद निवासी देवपासिया कटरा बाजार, जनपद गोंडा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक अन्य आरोपी अकबर अली पुलिस कार्रवाई के दौरान चकमा देकर भाग निकला, उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस ने जाफर के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस तथा मौके से गोवंश का मांस, बांका और रस्सी बरामद की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है तथा गोवध निवारण अधिनियम समेत अन्य सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

कौथिग में चंद्रप्रकाश के गीतों ने झुमाया

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तरायणी कौथिग के आठवें दिन बुधवार को उत्तराखंड के मशहूर लोकगायक चंद्रप्रकाश ने जोशीली प्रस्तुतियों से मन मोह लिया। मैं जांछू कमला काली गंगा पारा... और सोला सोल्यानी त्यार गाला जंजीरा... जैसे लोकगीतों ने समां बांध दिया। मिस उत्तरायणी निधि आर्या और मिस्टर उत्तरायणी शशांक सक्सेना को पर्वतीय महापरिषद के अध्यक्ष गणेश जोशी और युवा प्रकोष्ठ के वीरेंद्र आर्या ने सम्मानित किया। इस बार पद्मश्री प्रो. एमसी पंत चिकित्सा सम्मान ख्यातिप्राप्त नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. विनीत साह को दिया गया। क्षेत्रीय शाखाओं की नृत्य प्रस्तुतियों,

झोड़ा प्रतियोगिताएं और पहाड़ी धुनों पर देसी ठुमका प्रतियोगिता, झूमिगो सीजन–4 का भी आयोजन किया गया। इनमें पंतनगर, इंदिरानगर, गोमती नगर, रामलीला समिति तेलीबाग और माही वेलफेयर सोसाइटी शक्तिनगर की टीमों ने भाग लिया। हल्द्वानी से आए म्यूजिकल ग्रुप ने भी रंग जमाया। लोकगाथा पर आधारित नृत्य नाटिका श्श्माधो सिंह भंडारीश्श का मंचन दमयंती नेगी के निर्देशन में हुआ। मुख्य अतिथि दिल्ली के विधायक मोहन सिंह बिष्ट और विशिष्ट अतिथि ओंकार सिंह रहे। अपर मुख्य सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार लीना जौहरी को भी सम्मानित किया गया।

संक्षिप्त खबरें

शटर बंदकर 40 मिनट तक नारेबाजी

लखनऊ, (संवाददाता)। काकोरी कस्बा पुलिस चौकी के पास स्थित एसबीआई शाखा में एक करोड़ से अधिक की ठगी के मामले में बुधवार सुबह खाताधारकों का गुस्सा फूट पड़ा। करीब 10 बजे 40 से अधिक पीड़ितों ने बैंक का शटर बाहर से बंद कर दिया। उस समय बैंक मैनेजर समेत कई बैंक कर्मी अंदर मौजूद थे। खाताधारकों ने कहा कि जब तक जिम्मेदार बैंक कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती, कामकाज नहीं होने देंगे। पीड़ितों ने करीब 40 मिनट तक बैंक के बाहर नारेबाजी की। पुलिस ने जांच व कार्रवाई का आश्वासन देकर शटर खुलवाया। पीड़ितों का आरोप है कि उनकी जमा पूंजी खातों से गायब हो गई है, लेकिन एक महीने बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। भट्ठा टोला निवासी कुसमा ने बताया कि उन्होंने पांच लाख रुपये किस्तों में जमा किए थे, लेकिन खाते में एक भी रुपया नहीं मिला। टिकरिया गांव निवासी प्रदीप के तीन लाख रुपये, सागर तालाब निवासी माया के 50 हजार, गुरदीन खेड़ा निवासी रामा देवी के 30 हजार, राजकुमारी के 30 हजार समेत कई लोगों के रुपये गायब हैं। इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर ने बताया विवेचना में अब तक एक करोड़द्द से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। पहले 131 पीड़ितों की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। नईं शिकायतें भी जांच में शामिल की जा रही हैं।

लोक निर्माण विभाग मिनिस्टीरियल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने शैलेंद्र

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्टीरियल एसोसिएशन के जिला पदाधिकारियों का चुनाव बुधवार को संपन्न हुआ। चुनाव में शैलेंद्र कुमार यादव को जिलाध्यक्ष चुने गए। लोक निर्माण विभाग परिसर में हुए चुनाव में लोक निर्माण विभाग सर्किल एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष सुनील यादव और उपाध्यक्ष पारसनाथ आर्य ने पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। चुनाव अधिकारी कौशलेंद्र सिंह यादव ने बताया कि अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव पद पर आपसी सहमति से चुनाव हुआ। विनोद कुमार चौधरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, फरजान खां उपाध्यक्ष, सुधीर कुमार भारतीय सचिव चुने गए। रंजीत कुमार ने कार्यकारी अध्यक्ष, शुभम यादव ने संयुक्त सचिव, राजकुमार सिंह ने संगठन सचिव, अचर्ना श्रीवास्तव ने संगठन सचिव (महिला), दिग्विजय सिंह मौर्य ने वित्त सचिव और अमन यादव ने सम्प्रेक्षक के पद की शपथ ली।

रेलवे में नौकरी के लिए कुली चलाएंगे अभियान

लखनऊ, (संवाददाता)। कुली अब रेलवे में स्थायी नौकरी देकर समायोजित करने, उनके लिए चलाई जा रही शिक्षा, स्वास्थ्य, वर्दी, विश्रामगृह आदि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने व निजीकरण के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चलाएंगे। यह निर्णय बुधवार को राष्ट्रीय कुली मोर्चा की वर्चुअल बैठक में लिया गया। मोर्चा के संयोजक रामसुरेश यादव ने बताया कि बृहस्पतिवार दोपहर अभियान शुरू होगा। सोशल मीडिया एक्स पर रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और रेलवे बोर्ड के पदाधिकारियों को टैग कर पोस्ट किए जाएंगे। बजट सत्र से पहले सरकार का ध्यान कुलियों की आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के सवाल पर आकर्षित है।

गोमती से छल...निरीक्षण में बंद मिला हाथी पार्क का एसटीपी

लखनऊ, (संवाददाता)। नाले के गंदे पानी और सीवर को शोधित करने के लिए करीब पांच वर्ष पहले हाथी पार्क में स्थापित डेढ़ एमएलडी

क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) चल नहीं रहा था। जिम्मेदारों को इसकी खबर तक नहीं थी। बीते दिनों प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम के निरीक्षण में एसटीपी बंद मिला। इसके बाद अब बोर्ड ने संचालन करने वाली फर्म शिवाय कंस्ट्रक्शन को नोटिस जारी किया है। नगर निगम को भी रिपोर्ट भेजी है।उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के क्षेत्रीय अधिकारी जेपी मौर्य की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि 25 दिसंबर को निरीक्षण के दौरान एसटीपी बंद मिला था। ऐसा क्यों है? संचालन के संबंध में पत्र जारी करने के बाद भी कोई जानकारी क्यों नहीं दी गई? पत्र के मुताबिक, 13 जनवरी को बोर्ड के सहायक पर्यावरण अभियंता ने एक बार फिर निरीक्षण किया। उस दौरान भी एसटीपी बंद मिला। जानकारी करने पर वहां मौजूद प्रतिनिधि ने बताया कि सीवेज को भरवारा एसटीपी में शोधित करने के लिए सीवेज पंपिंग स्टेशन भेजा जा रहा है। ऐसी स्थिति में अधिक सीवेज आने पर उसका सीधे गोमती नदी में जाना स्वाभाविक है। यह एसटीपी मेडिकल कॉलेज व आसपास इलाके के गंदे पानी व सीवेज ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है। नोटिस में फर्म को चेतावनी भी दी गई है कि यदि तीन दिन में जवाब न दिया तो पर्यावरणीय अधिनियमों के तहत कार्रवाई की रिपोर्ट अधिकारियों को भेज दी जाएगी। इसमें जुर्माना लगाने और काम से हटाने तक की कार्रवाई हो सकती है।

रामलला को भेंट किया गया भव्य स्वर्ण कोदंड, कारगिल युद्ध शहीदों के नाम अंकित 48 महिलाओं ने तैयार किया

लखनऊ, (संवाददाता)। रामनगरी अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर में विराजमान रामलला को भव्य श्स्वर्ण कोदंडश भेंट किया गया है। रामलला की प्राण–प्रतिष्ठा को दो वर्ष पूरे हो गए हैं। प्राण–प्रतिष्ठा के बाद से राम मंदिर में देशभर से श्रद्धालुओं की ओर से अनुपम उपहार भेंट किए जा रहे हैं। तीसरे वर्ष की शुरुआत में बृहस्पतिवार को रामलला के लिए एक और ऐतिहासिक और अद्वितीय भेंट श्स्वर्ण कोदंडश रामनगरी लाई गई है। भव्य धनुष श्स्वर्ण कोदंडश पहले कारसेवकपुरम में रखा गया, फिर राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया गया। यह अनमोल भेंट पंचधातु से बना है। इसका वजन 286 किलोग्राम है। ओडिशा के राउरकेला से तीन जनवरी 2026 को इस कोदंड की भव्य शोभायात्रा अयोध्या के लिए रवाना हुई थी। शोभायात्रा सनातन जागरण मंच की ओर से आयोजित की गई। यह शोभायात्रा ओडिशा

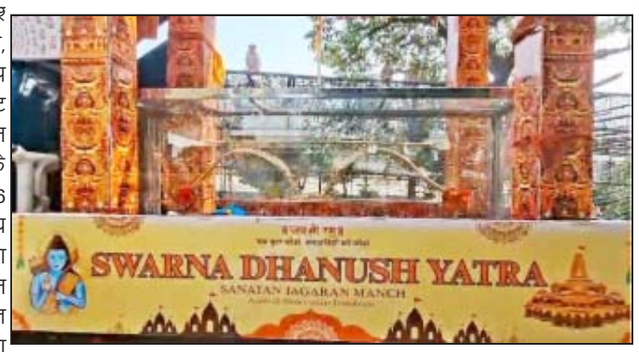

के सभी 30 जिलों से होकर गुजरी। 19 जनवरी को पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन–पूजन के बाद आगे बढ़ी। 22 जनवरी को प्राण–प्रतिष्ठा की तिथि के पावन संयोग पर यह कोदंड अयोध्या पहुंचा। यहां रामलला को समर्पित किया गया। पंचधातु से बने इस कोदंड में सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और लोहे का प्रयोग हुआ है। तमिलनाडु के कांचीपुरम की 48 महिला कारीगरों ने आठ महीने की मेहनत से इसे तैयार किया है। लगभग आठ फीट लंबे इस कोदंड पर ऑपरेशन सिंदूर की सैन्य वीरता और कारगिल युद्ध शहीदों के नाम अंकित हैं। इसकी अनुमानित लागत करीब सवा करोड़ रुपये बताई जा रही है।

संक्षिप्त खबरें

निजी केंद्रों पर निशुल्क जांच करा सकेंगे कल्याण सिंह कैंसर संस्थान के मरीज

लखनऊ, (संवाददाता)। कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान के मरीज अब निजी डायग्नोस्टिक केंद्रों पर भी निशुल्क जांच करा सकेंगे। इसके लिए संस्थान ने पांच निजी केंद्रों से समझौता किया है। इसके बाद मरीजों को जांच के लिए इंतजार नहीं करना होगा। संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. वरुण विजय ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत संबद्ध निदान केंद्रों पर उपलब्ध सभी जांच अब आयुष्मान भारत योजना के तहत निर्धारित दरों पर ही की जाएंगी। ये सेवाएं कैश और कैशलेस दोनों ही माध्यमों में उपलब्ध होंगी। इसका सीधा लाभ कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान के सभी रोगियों को मिलेगा। इससे उनके इलाज का बोझ काफी हद तक कम हो सकेगा। संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. विजेंद्र कुमार और चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. वरुण विजय की उपस्थिति में यह समझौता हुआ। चरक डायग्नोस्टिक्स एवं चरक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शान्या ग्लोबल स्कैनिंग एंड रिसर्च, ग्लोब मेडिकेयर डायग्नोस्टिक्स, सरकार मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर और श्री राम मूर्ति स्मारक फंक्शनल इमेजिंग एंड मेडिकल सेंटर।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने आयोजित की समाज कल्याण योजनाओं पर कार्यशाला

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने आज राजधानी लखनऊ में ''समाज कल्याण विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं'' पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता आयोग की माननीय अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. बबीता सिंह चौहान, माननीय उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी, आयोग के माननीय सदस्यों तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी सुश्री शिल्पी सिंह और श्री नदीम सिद्दीकी द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया।कार्यशाला में समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं, उनके प्रशिक्षण और लाभ के बारे में व्यापक जानकारी दी गई। सुश्री शिल्पी सिंह ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, अनुसूचित जाति के अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आर्थिक सहायता योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण योजना, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन, अनुसूचित जाति छात्रावास, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड और माता–पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण और वृद्धाश्रम संचालन से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की।कार्यशाला के दौरान आयोग के पदाधिकारियों ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आगामी जनसुनवाई और जागरूकता चौपालों में महिलाओं और बालिकाओं को इन योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने पर विशेष जोर दिया।कार्यक्रम के दूसरे सत्र में आयोग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पूर्व में आयोजित मिशन–शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं की जनसुनवाई, निरीक्षण कार्यक्रम और पोषण पंचायत कार्यक्रम की समीक्षा की गई। आयोग ने यह सुनिश्चित करने पर बल दिया कि प्रदेश की महिलाओं को सभी कल्याणकारी योजनाओं से त्वरित और प्रभावी लाभ प्राप्त हो।कार्यक्रम में आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान, उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी, सदस्यगण श्रीमती हिमानी अग्रवाल, श्रीमती संगीता जैन सहित अन्य गणमान्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मौनी अमावस्या पर संतों, बटुकों को पीटना कही कोई षडयंत्र तो नहीं इसका निष्पक्ष जांच सीबीआई जांच होनी चाहिए : चक्रपाणि जी महाराज

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। सनातन सम्राट परमपूज्य स्वामी चक्रपाणि महराज जी अखिल भारतीय हिंदू महासभा , संत महासभा, श्री चित्रगुप्त भगवान अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सनातन की पहचान कुंभ माघ मेला में मौनी अमावस्या संतों, बटुकों को पीटना कही कोई षड्यंत्र तो नहीं सनातन सम्राट योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश तो नहीं इसका निष्पक्ष जांच सीबीआई जांच होनी चाहिए। स्वामी चक्रपाणि महराज जी ने जौनपुर श्री चित्रगुप्त भगवान मंदिर रूहटा में पत्रकार वार्ता एवं हिन्दू महासभा, कायस्थ महासभा 7235 भारत, संत महासभा द्वारा आयोजित बसंत पंचमी उत्सव,नेता जी सुभाष चंद्र बोस जयंती, में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए स्वामी चक्रपाणि महराज जी ने कहा कहा कि हम देश के युवाओं से कहना चाहते है कि युवा अपना आदर्श नेताजी सुभाष चन्द्र बोस व स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श माने जिन्होंने ने राष्ट्रहित में सदैव कार्य किया नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कर देश को आजादी दिलाने में बड़ा योगदान दिया था। स्वामी चक्रपाणि जी ने कहा कि शीघ्र ही उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदू सनातन यात्रा निकाली जाएगी जो पूरे मंदिर को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करेगी। आए दिन सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है जिससे सजग रहने की जरूरत है सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र के लिए संकल्पित है और रहेगा और कुछ लोग हमारी सनातन परम्परा बदनाम की साजिश करते है ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है इसकी जाँच होनी चाहिए भले ही सनातन हिंदू अलग अलग जाति में विभाजित है लेकिन सब हिन्दू एक है और रहेंगे। लव जिहाद व धर्मांतरण मामले में सख्त कानून बनना चाहिए। गौरक्षा कानून होना चाहिए , और कहा कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की फोटो नोटों होनी चाहिए।कहा है कि आज धार्मिक स्वाभिमान को बचाने की जरूरत है। सनातन परम्पराओं में व्यवधान डाला जा रहा है। इसका डटकर मुकाबला करना चाहिए तभी हिन्दू समाज के समाज के अस्तित्व की रक्षा हा सकती है। और कहा कि गरीबों की सेवा सेवा और देश के सेवा में अपने जान गंवाने वालों का मोक्ष मिलता हे और वे अमर हो जाते है। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्टवादी हिन्दू परंपराओं पर चोट पहुंचा रहे है, ऐसा त्रेता युग में भी हुआ था। ऋषियों के यज्ञ पूजन में व्यवधान डाला जाता था तब राम चन्द्र जी ने राक्षसों का संहार किया था। उन्होंने कहा कि आस्था पर कुठाराघात बर्दाश्त नहीं करना चाहिए उसका सामना करना चाहिए परिणाम कुछ भी हो। स्वामी जी ने कहा कि देश में चरित्र की पूजा होती है चित्र की नहीं। भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत प्रजापति ने स्वामी चक्रपाणि महराज जी का स्वागत करते हुए कहा कि आज बसंत पंचमी उत्सव पर स्वामी जी का जौनपुर आगमन से जौनपुर जनपद में हर्ष व्याप्त है। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव साधु, प्रदेश अध्यक्ष कायस्थ महासभा दिनेश चन्द श्रीवास्तव दीनू ने कहा है आज नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रेरणा से कायस्थ महासभा 7235 जौनपुर ने एक युवाओं की फौज खड़ी कर दी है जो समाजहित राष्ट्रहित में कार्य कर रहा

है। स्वामी चक्रपाणि महराज जी ने राजेश श्रीवास्तव बच्चा भईया एडवोकेट को प्रदेश संयोजक श्री चित्रगुप्त भगवान अखाड़ा परिषद उत्तर प्रदेश मनोनीत किया और आदेशित किया कि बच्चा भईया पूरे प्रदेश में संगठन का गठन करेंगे। उक्त अवसर पर डॉ उमाकांत श्रीवास्तव, रमेंद्र नाथ श्रीवास्तव, दयाल सरन, विनय श्रीवास्तव, चंद्रमोहन श्रीवास्तव,गिरिजेश कुमार, देवेंद्र श्रीवास्तव मोहन शंकर श्रीवास्तव, विश्व प्रकाश श्रीवास्तव दीपक पत्रकार, अंकित श्रीवास्तव,अमित निगम बजरंग प्रसाद श्रीवास्तव,,शशि राज सिन्हा, डॉ संजय श्रीवास्तव,डॉ जितेंद्र श्रीवास्तव, राकेश श्रीवास्तव, दयाशंकर निगम,गौरव श्रीवास्तव राजा,अजय वर्मा अज्जू, संतोष श्रीवास्तव सोनू, पीयूष गुप्ता, मनोज श्रीवास्तव, आदि उपस्थित रहे। इससे पूर्व स्वामी चक्रपाणि महराज जी का जौनपुर आगमन पर जगह जगह बैंड बाजा माला फूल बुके भेट कर जोरदार स्वागत अभिनंदन किया गया और पॉलिटिनिक चौराहे से युवाओं के नेतृत्व सैकड़ों दुपहिया वाहन जुलुश के साथ श्री चित्रगुप्त मंदिर रूहटा तक गए।

उत्तर प्रदेश में कृषि विकास और शिक्षा को मिले वित्तीय प्रोत्साहन

लखनऊ, (संवाददाता)। 6उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने, कृषकों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने और कृषि शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं। इन स्वीकृतियों से न केवल किसानों को सिंचाई और कृषि लागत में मदद मिलेगी, बल्कि कृषि विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र–छात्राओं को बेहतर सुविधाएं भी सुनिश्चित होंगी।कृषि उत्पादन में वृद्धि के संकल्प के अनुरूप, शासन ने कृषकों के निजी नलकूपों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को जनवरी 2026 से मार्च 2026 की अवधि के लिए 60,000.00 लाख रुपये (छः अरब रुपये) की वित्तीय स्वीकृति दी है। इस धनराशि का उपयोग किसानों को विद्युत सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए किया जाएगा, जिससे कृषि लागत में कमी आएगी और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।कृषि शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अधीन संचालित कृषि महाविद्यालय, हरदोई परिसर में 75 कमरों के आधुनिक बालक छात्रावास के निर्माण हेतु 1832.12 लाख रुपये (अट्ठारह करोड़ बत्तीस लाख बारह हजार रुपये) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय, आजमगढ़ में विभिन्न कार्यों के संचालन हेतु 50 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2025–26 के लिए अनुदान संख्या–11 के अंतर्गत संचालित कृषि उत्पादन वृद्धि योजना हेतु 430.00 लाख रुपये (चार करोड़ तीस लाख रुपये) की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में डिजिटल क्रांति की शुरुआत, लखनऊ की दो पंचायतों से शुरू हुई आधार सेवाएं

लखनऊ, (संवाददाता)। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप और पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में पंचायती राज विभाग प्रदेश की ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रहा है। इसी क्रम में ग्राम स्तर पर आधार सेवाओं की शुरुआत करते हुए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक डिजिटल पहल को धरातल पर उतारा गया है, जिससे ग्रामीण नागरिकों को सीधे अपने गांव में ही महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है।प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्लॉक सरोजनीनगर की ग्राम पंचायत भटगनवां पांडेय तथा चिनहट ब्लॉक की सैरपुर ग्राम पंचायत में आधार सेवाएं सफलतापूर्वक प्रारंभ कर दी गई हैं। इन दोनों ग्राम पंचायतों में अब तक 40 से अधिक ग्रामीण नागरिकों को आधार से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। इस सुविधा के शुरू होने से ग्रामीणों को अब आधार अपडेट, संशोधन और अन्य सेवाओं के लिए शहरों या दूरस्थ केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं, जिससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है।पंचायती राज विभाग की यह पहल पंचायत स्तर पर नागरिक सेवाओं की सहज, पारदर्शी और सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा और दूरगामी कदम मानी जा रही है। विभाग की योजना के अनुसार पहले चरण में प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में आधार सेवाएं शुरू की जाएंगी। इसके बाद इस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से प्रदेश की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों तक विस्तारित किया जाएगा, ताकि हर गांव के नागरिकों को डिजिटल सेवाओं का सीधा लाभ मिल सके।इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत सहायकों का व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। अब तक 800 से अधिक पंचायत सहायकों को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जबकि शेष पंचायत सहायकों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया तेजी से जारी है। प्रशिक्षित पंचायत सहायक ग्राम स्तर पर नागरिकों को आधार सेवाएं उपलब्ध कराकर पंचायतों को एक सशक्त सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।इस अवसर पर पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ग्राम स्तर पर आधार सेवाओं की शुरुआत ग्रामीणों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह पहल न केवल समय और संसाधनों की बचत करेगी, बल्कि ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह ने कहा कि विभाग ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आधार सेवाओं की यह शुरुआत पंचायतों को नागरिक सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी और आने वाले समय में इसका लाभ प्रदेश के हर गांव तक पहुंचेगा।ग्राम पंचायत स्तर पर आधार सेवाओं की यह पहल डिजिटल इंडिया के संकल्प और सशक्त पंचायतों की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक सफल, प्रेरणादायक और परिवर्तनकारी शुरुआत मानी जा रही है, जो भविष्य में ग्रामीण प्रशासन और सेवा वितरण की तस्वीर को पूरी तरह बदलने वाली है।

नेताजी का योगदान स्वतंत्रता संग्राम का स्वर्णिम अध्याय है : कुलपति प्रो. वंदना सिंह

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती एवं उत्तर प्रदेश दिवसद्2026 के अवसर पर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में शुक्रवार को "देश के नाम पदयात्रा" का भव्य आयोजन किया गया। यह पदयात्रा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार सरस्वती सदन से प्रारंभ होकर रोवर्सदृरेंजर्स भवन में स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा तक निकाली गई। संकाय भवन में विकसित उत्तर प्रदेश– विकसित भारत विषय पर रंगोली प्रतिओगिता का भी आयोजन किया गया. पदयात्रा का शुभारंभ विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह एवं एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर आलोक सिंह धर्मराज द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। राष्ट्रभक्ति के नारों और देशभक्ति गीतों के साथ निकली पदयात्रा से पूरा विश्वविद्यालय परिसर देशप्रेम से गूंज उठा। रोवर्सदृरेंजर्स भवन पहुंचने पर सभी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर कुलपति प्रो. वंदना सिंह ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का स्वर्णिम अध्याय है। उनका त्याग, साहस और राष्ट्रभक्ति युवाओं के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर आलोक सिंह धर्मराज ने कहा कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज के गठन के माध्यम से देशवासियों में राष्ट्रप्रेम की भावना को जागृत कर आजादी के संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। कार्यक्रम का समन्वय उत्तर प्रदेश दिवसद्2026 के समन्वयक प्रो. प्रदीप कुमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. दिग्विजय सिंह राठौर, सह–नोडल अधिकारी डॉ. अन्नू त्यागी एवं शशिकांत यादव रहे। यह आयोजन विश्वविद्यालय एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) एवं रोवर्सदृरेंजर्स के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री केशलाल, परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार सिंह, रोवर्सदृरेंजर्स के मुख्य आयुक्त प्रोफेसर शंभू नाथ, उप कुलसचिव श्री अजीत कुमार सिंह, प्रो. अजय प्रताप सिंह, प्रो. अविनाश, प्रो. मनोज मिश्र, प्रो. गिरिधर मिश्र, डॉ. जाह्नवी श्रीवास्तव, डॉ. श्याम कन्हैया सिंह, डॉ. चंदन सिंह, डॉ. सहित एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) एवं रोवर्सदृरेंजर्स के स्वयंसेवकों तथा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के छात्र–छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।इसी क्रम में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर मां सरस्वती की प्रतिमा पर श्रद्धापूर्वक माल्यार्पण कर पूजा–अर्चना की गई। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह, कुल सचिव केशलाल, परीक्षा नियंत्रक विनोद कुमार सिंह सहित विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती से ज्ञान, विवेक एवं सद्बुद्धि की कामना की गई।

चाइनीज मांझे का कहर जारी है अधिवक्ता चपेट में गर्दन पर गंभीर चोट हॉस्पिटल में भर्ती

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में चाइनीज मांझे का कहर जारी है। शुक्रवार सुबह सद्भावना पुल पर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक सरकारी अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। भंडारी स्टेशन निवासी पूर्व शासकीय अधिवक्ता हरीश चंद्र मौर्या सुबह करीब 10 बजे अपनी बाइक से दीवानी न्यायालय जा रहे थे। सद्भावना पुल के पास अचानक मांझा उनके गले में फंस गया, जिससे उनकी गर्दन की चमड़ी कट गई और खून बहने लगा। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। जिला प्रशासन द्वारा चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद, दुकानदार बेखौफ होकर इसे बेच रहे हैं, जिसके कारण ऐसी जानलेवा घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इससे पहले, 14 जनवरी को केराकत निवासी डॉ. समीर हाशमी की चाइनीज मांझे की चपेट में आने से मौत हो गई थी। वे अपना काम निपटाकर

जिले से केराकत स्थित अपने क्लिनिक जा रहे थे, तभी प्रसाद तिराहे के पास मांझा उनके गले में फंस गया और उनकी गर्दन कटने से उनकी जान चली गई। इसी तरह, 10 दिसंबर को शिक्षक संदीप तिवारी भी अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर घर लौट रहे थे। शाही पुल के पास अचानक चाइनीज मांझा उनकी गर्दन में फंस गया, जिससे उनकी गर्दन कट गई और उनकी भी मौत हो गई थी। इस संबंध में जानकारी लेने पर क्षेत्राधिकारी सदर देवेश कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है मांझा प्रतिबंधित है।

संक्षिप्त खबरें

'जिलाधिकारी ने जनसुनवाई में जनता की समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिये निर्देश।'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहांपुर' जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में आमजन की समस्याएं सुनीं। जिलाधिकारी ने जनसुनवाई के

दौरान प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया और कहा कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक नागरिक की समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत पर सजी अकीदत की महफिल

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर । हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के पावन अवसर पर खुटहन थाना क्षेत्र के शेखपुर गांव स्थित रौजा–ए–इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर भव्य रूप से जश्ने सफीनतुननिजात का आयोजन किया गया। इस मौके पर अकीदतमंदों की बड़ी मौजूदगी के बीच पूरी फिजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और जिक्र से गूंज उठी। महफिल की अध्यक्षता मौलाना शाजान जैदी ने की, जबकि हदीसे किसा की तिलावत मौलाना अहमद हसन खान द्वारा किया गया , उनके कलाम ने मौजूद श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। महफिल को खिताब करते हुए हजरत मौलाना अम्बर अब्बास खान ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पाक सीरत

पर विस्तार से रोशनी डाली, उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिन्दगी इंसाफ, सब्र, कुर्बानी और हकद के लिए डटकर खड़े होने का पैगाम देती है । उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पदचिन्हों पर चलते हुए समाज में अमन, भाईचारा और इंसानियत को मजबूत करें । महफिल में शायरी का भी खघस आयोजन रहा, जिसमें तनवीर जौनपुरी, फहमी इमामपुरी , रोमान इमामपुरी ,गुलफाम इमामपुरी ,अबुजर गौसपुरी , रेहान इमामपुरी , अर्शी इमामपुरी , सलमान जौनपुरी , तालिब जौनपुरी, हसन जौनपुरी सहित अन्य शायरों ने बारगाह इमाम में नजराना–ए–अकधिदत पेश कर माहौल को और भी रूहानी बना दिया। कार्यक्रम का सफल संचालन अल्लामा बिलाल हसनैन ने किया, जिन्होंने पूरी महफिल को खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाया। इस अवसर पर अली हैदर , कल्बे हसन ,शुजा साहब , शबाब हैदर , मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद जफर , समर , शहनशाह हैदर सहित बड़ी संख्या में अकीदतमंद और क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। अंत में मुल्क में अमन–चौन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ के साथ महफिल का समापन किया गया। महफिल के समापन पर आयोजक मोहहमद जफर एवं मोहम्मद अब्बास ने आये हुए मोमनीन का शुक्रिया अदा किया ।

एलडीए की आईटी सिटी योजना 20 फरवरी को होगी लॉन्च

लखनऊ, (संवाददाता)। सुल्तानपुर रोड पर विकसित की जा रही एलडीए की आईटी सिटी योजना 20 फरवरी तक लॉन्च हो जाएगी। योजना में करीब 10 हजार भूखंड विकसित किए जा रहे हैं। पहले भूखंड उन लोगों को आवंटित किए जाएंगे, जिन्होंने योजना के लिए निशुल्क जमीन दी है। इसके बाद आम लोगों के लिए पंजीकरण खोला जाएगा। इस योजना में करीब एक लाख लोगों को आवासीय सुविधा मिलेगी। यहां पर जमीन की कीमत करीब चार हजार रुपये प्रति वर्ग फीट प्रस्तावित है। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि आईटी सिटी योजना सुल्तानपुर रोड व किसान पथ से सीधे जुड़ती है। करीब 3490 एकड़ में विकसित की जा रही इस योजना में 35 वर्ग मीटर से 288 वर्ग मीटर तक के भूखंड बनाए जा रहे हैं। यहां लैंड पूलिंग के जरिये जमीन जुटाई गई है जिसमें किसानों को उनकी कुल जमीन के बदले में 25 प्रतिशत विकसित जमीन दी जाएगी। 20 फरवरी को योजना लॉन्चिंग के मौके पर लॉटरी में किसानों को शामिल किया जाएगा जिनकी लैंड पूलिंग 27 जनवरी तक हो जाएगी। प्लॉट लॉटरी आवंटित किए जाएंगे। यह प्लॉट योजना के सेक्टर 15, 16, 17 व 18 में होंगे। योजना में लैंडपूलिंग के तहत अभी तक 275 भूस्वामियों ने 125 एकड़ अपनी जमीन योजना के लिए एलडीए को दी है। लॉटरी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मर्करी हाल में 20 फरवरी को होगी। जिन भूस्वामियों की लैंड पूलिंग 27 जनवरी के बाद होगी उनको दूसरे फेज में लॉटरी से प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। लैंड पूलिंग की प्रक्रिया की दूसरे फेज की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आम लोगों के लिए पंजीकरण खोला जाएगा जिसमें तीन महीने का समय लग सकता है।

शादी के नाम पर ठगी, गिरोह सक्रिय जौनपुर में युवक से लाखों रुपये ऐंठे, फर्जी दुल्हन फरार चार आरोपित गिरफ्तार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में सरायख्वजा थाना अंतर्गत पुलिस ने फर्जी ,धोखे से शादी कराकर पैसो की ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले का शुक्रवार को खुलासा करते हुए क्षेत्राधिकारी सदर देवेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने आदमपुर मोड़ के पास से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान 32 हजार 500 रूपये नकद भी बरामद किये गये है। पुलिस ने ब्रिजेश कुमार गौतम निवासी कौड़िया थाना शाहगंज , आशु गौतम निवासी ख्हौरा थाना सरायख्वाजा ,रुक्सार निवासी मीरपुर थाना जलालपुर आंबेडकरनगर और काजल निवासी मियापुर थाना लाइन बाजार शामिल है। संभल निवासी एक युवक विनोद कुमार को फर्जी दुल्हन का झांसा देकर लाखों रुपये ऐंठे और फिर फरार हो गए। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को पकड़ा है, जिसने पूछताछ में पूरी वारदात का खुलासा किया है। गिरोह का तरीका यह था कि वे अविवाहित पुरुषों के मोबाइल नंबर प्राप्त करते थे। फिर उनसे फोन पर संपर्क कर शादी का प्रस्ताव देते थे। इसके लिए वे अपनी ही सहयोगी लड़कियों की तस्वीरें भेजते थे और उन्हें शादी के लिए बुलाते थे। शादी के नाम पर खरीदारी कराते थे और पैसे ऐंठते थे। मामले के अनुसार, गिरोह को संभल के टंकी मोहल्ला, थाना धिन्नौर कोतवाली निवासी विनोद कुमार पुत्र गजराम के बारे में जानकारी मिली। विनोद शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहे थे। गिरोह ने उनके साले, जिनकी ससुराल बहाउद्दीनपुर, थाना सरायख्वाजा, जौनपुर में है, के माध्यम से विनोद से संपर्क साधा। इसके बाद, गिरोह ने अपनी सहयोगी नेहा की तस्वीर भेजकर विनोद को शादी के लिए बुलाया। विनोद अपने साले के साथ मल्हनी बाजार पहुंचे, जहां गिरोह के सदस्यों ने उनसे शादी की खरीदारी और अन्य खर्चों के नाम पर पैसे मांगे। विनोद ने बताया कि उनका भाई पैसे भेजेगा। गिरोह विनोद को जन सेवा केंद्र ले गया, जहां स्कैनर के माध्यम से विनोद ने अपने भाइयों से पैसे मंगवाए। पैसे मिलने के बाद, गिरोह ने वह रकम आपस में बांट ली और कुछ सामान खरीदे। इसके बाद नेहा और विनोद को मल्हनी के एक मंदिर में ले जाकर उनकी झूठी शादी करवाई गई। शादी के बाद, जब वे विनोद को ट्रेन पकड़वाने के लिए जौनपुर स्टेशन जा रहे थे, तो रास्ते में कुत्तूपुर के पास विनोद को पानी लेने के लिए भेजा गया। विनोद के जाते ही गिरोह नेहा को लेकर वहां से फरार हो गया। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि विनोद से मिली रकम उन्होंने खर्च कर दी थी। उसके पास से 32,500 रुपये बरामद हुए हैं, जबकि शेष पैसे सचिन और नेहा के पास होने की बात कही गई है। आरोपी ने स्वीकार किया कि उन्होंने पहले भी छतरपुर, अंबेडकर नगर और जौनपुर सहित कई स्थानों पर ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दिया है।

पुलिस सतर्क मित्र व्हाट्स बोट लॉन्च , पुलिस को सरल तरीके से मिलेगी जानकारी:अपर पुलिस महानिदेशक

ब्यूरोप्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में पुलिस लाईन सभागार में शुक्रवार को वर्चुवल मीटिंग के माध्यम से वाराणसी के अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोड़ीया ने श्पुलिस सतर्क मित्रश वॉट्सऐप बोट लॉन्च किया है। यह पहल नागरिकों को अपने आसपास हो रही अवैध गतिविधियों की सूचना पुलिस को सरल, सुरक्षित और गोपनीय तरीके से उपलब्ध कराने में मदद करेगी। श्पुलिस सतर्क मित्रश एक ऑटोमेटेड वॉट्सऐप चौटबोट है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को गुमनाम रूप से अपराध की जानकारी देने, पुलिस तक तेज एवं विश्वसनीय सूचना पहुँचाना और जनता तथा पुलिस के बीच सुरक्षित एवं प्रभावी संवाद स्थापित करना है। इस सेवा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सूचना देने वाले नागरिक की पहचान (नाम या फोन नंबर) पुलिस को प्रदर्शित नहीं होती। इससे नागरिक बिना किसी भय के अवैध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दे सकते हैं। नागरिक गौ तस्करी, गोहत्या, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियार, जुआ, सट्टा, महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध, मानव तस्करी, पुलिस भ्रष्टाचार और अवैध खनन जैसी विभिन्न गतिविधियों से संबंधित शिकायतें या सूचनाएं दे सकते हैं। इस सेवा का उपयोग करना अत्यंत सरल है और इसके लिए किसी अलग ऐप को इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। नागरिक अपने मोबाइल से वॉट्सऐप खोलकर नंबर 7839860411 पर "भ्प" या कोई भी संदेश भेज सकते हैं। बोट द्वारा पूछी गई भाषा (हिंदीध्अन्य) का चयन करने के बाद, समय, स्थान और अपराध ा के प्रकार से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट, ऑडियो, फोटो अथवा वीडियो (जैसे सीसीटीवी फुटेज) भी भेजे जा सकते हैं। प्राप्त सूचना का पुलिस द्वारा परीक्षण किया जाता है और आवश्यक कार्रवाई की जाती है। सूचना देने वाले को स्वचालित फीडबैक भी प्राप्त होता है। जनपद पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे श्पुलिस सतर्क मित्रश वॉट्सऐप बोट का अधिक से अधिक उपयोग कर अपराध नियंत्रण एवं कानून–व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।

संक्षिप्त खबरें

मौनी अमावस्या पर संतों, बटुकों को पीटना कही कोई षड्यंत्र तो नहीं इसका निष्पक्ष जांच सीबीआई जांच होनी चाहिए : चक्रपाणि जी महाराज

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। सनातन सम्राट परमपूज्य स्वामी चक्रपाणि महराज जी अखिल भारतीय हिंदू महासभा , संत महासभा, श्री चित्रगुप्त भगवान अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सनातन की पहचान कुंभ माघ मेला में मौनी अमावस्या संतों, बटुकों को पीटना कही कोई षड्यंत्र तो नहीं सनातन सम्राट योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश तो नहीं इसका निष्पक्ष जांच सीबीआई जांच होनी चाहिए। स्वामी चक्रपाणि महराज जी ने जौनपुर श्री चित्रगुप्त भगवान मंदिर रूहटा में पत्रकार वार्ता एवं हिन्दू महासभा, कायस्थ महासभा 7235 भारत, संत महासभा द्वारा आयोजित बसंत पंचमी उत्सव,नेता जी सुभाष चंद्र बोस जयंती, में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए स्वामी चक्रपाणि महराज जी ने कहा कहा कि हम देश के युवाओं से कहना चाहते है कि युवा अपना आदर्श नेताजी सुभाष चन्द्र बोस व स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श माने जिन्होंने ने राष्ट्रहित में सदैव कार्य किया नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कर देश को आजादी दिलाने में बड़ा योगदान दिया था। स्वामी चक्रपाणि जी ने कहा कि शीघ्र ही उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदू सनातन यात्रा निकाली जाएगी जो पूरे मंदिर को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करेगी। आए दिन सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है जिससे सजग रहने की जरूरत है सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र के लिए संकल्पित है और रहेगा और कुछ लोग हमारी सनातन

परम्परा बदनाम की साजिश करते है ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है इसकी जॉच होनी चाहिए भले ही सनातन हिंदू अलग अलग जाति में विभाजित है लेकिन सब हिन्दू एक है और रहेंगे। लव जिहाद व धर्मांतरण मामले में सख्त कानून बनना चाहिए। गौरक्षा कानून होना चाहिए , और कहा कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की फोटो नोटों होनी चाहिए।कहा है कि आज धार्मिक स्वाभिमान को बचाने की जरूरत है। सनातन परम्पराओं में व्यवधान डाला जा रहा है। इसका डटकर मुकाबला करना चाहिए तभी हिन्दू समाज के समाज के अस्तित्व की रक्षा हा सकती है। और कहा कि गरीबों की सेवा सेवा और देश के सेवा में अपने जान गंवाने वालों का मोक्ष मिलता हे और वे अमर हो जाते है। जन में व्यवधान डाला जाता था तब राम चन्द्र जी ने राक्षसों का संहार किया था। उन्होंने कहा कि आस्था पर कुठाराघात बर्दाश्त नहीं करना चाहिए उसका सामना करना चाहिए परिणाम कुछ भी हो। स्वामी जी ने कहा कि देश में चरित्र की पूजा होती है चित्र की नहीं।

भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत प्रजापति ने स्वामी चक्रपाणि महराज जी का स्वागत करते हुए कहा कि आज बसंत पंचमी उत्सव पर स्वामी जी का जौनपुर आगमन से जौनपुर जनपद में हर्ष व्याप्त है। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव साधु, प्रदेश अध्यक्ष कायस्थ महासभा दिनेश चन्द श्रीवास्तव दीनू ने कहा है आज नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रेरणा से कायस्थ महासभा 7235 जौनपुर ने एक युवाओं की फौज खड़ी कर दी है जो समाजहित राष्ट्रहित में कार्य कर रहा है।

काकोरी-ऐक्शन शताब्दी वर्ष आयोजन समिति ने मनाया नेताजी सुभाषचंद्र बोस की 129वीं जयंती

ब्यूरोप्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर आजादी आन्दोलन के गैर समझौतावादी धारा के महानायक नेताजी सुभाषचंद्र बोस की 129वीं जयंती के अवसर पर काकोरी–ऐक्शन शताब्दी वर्ष आयोजन समिति जौनपुर की ओर से आज 23 जनवरी 2026 को बाईक जुलूस व जन सभा का आयोजन किया गया। बाईक जुलूस की शुरुआत सिंगरामऊ से की गई, जो कुशहां, बटाऊबीर, बदलापुर, कलिंजरा होते हुए तेजीबाजार तक गया। दूसरा बाइक जुलूस सराय पड़री से शुरु करके गद्दोपुर, महराजगंज, लोहिंदा होते हुए तेजीबाजार तक गया। दोनों बाइक जूलूसों के पहुंचने के बाद तेजीबाजार मेंनेताजी सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा के समक्ष जन सभा हुई। जिसमें काफी संख्या में छात्र नौजवानों ने भाग लिया। जन सभा शुरु होने के पहले नेताजी सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा पर सैकड़ों लोगों ने माल्यार्पण किए। इस अवसर पर राष्ट्रवादी नौजवान सभा के पदाधिकारी व कार्यकर्तागण भी मौजूद रहे। जन सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आजादी आंदोलन में नेताजी सुभाषचंद्र बोस का जीवन कठिन संघर्षों से भरा रहा। वे बचपन में अपने घर के पास रास्ते में रोजाना एक बूढ़ी मां को भीख मांगते देखकर द्रवित जाते और अपने स्कूल का टिफिन प्रतिदिन दे देते और सोचा करते कि कब हमारे समाज से इस तरह की गैर बराबरी खत्म होगी। दूसरी घटना, जो उन्हें प्रभावित किया, वह थी महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की सबसे कम उम्र में फांसी। इसके अलावा आस–पास हो रहे अन्याय–अत्याचार देखकर उनके मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत पैदा हो गई। उन्होंने कहा था– ष्झूठ और अन्याय के साथ समझौता करना जघन्यतम अपराध है।ष इस तरह राजनैतिक संघर्ष में जब वे 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गये, तो उन्होंने आह्वान किया कि ष्हमारा पहला लक्ष्य है पूर्ण स्वराज्य हासिल करना और उसके बाद भारत में समाजवाद कायम करना।ष इसीलिए उन्होंने कहा था– ष्मैं अपने बचपन में अंग्रेजों को देश से खदेड़ देना ही सबसे बड़ा कर्त्तव्य समझता था। लेकिन बाद में सोचकर देखा कि अंग्रेजों को खदेड़ देने मात्र से ही हमारे कर्त्तव्य समाप्त नहीं हो जायेंगे। भारत में नयी समाज व्यवस्था लागू करने के लिए एक और क्रांति की जरूरत होगी। लेकिन आजादी के 78 वर्षों के बाद भी नेताजी सुभाषचंद्र बोस सहित हमारे देश के तमाम महान स्वतंत्रता सेनानियों व क्रांतिकारियों का सपना पूरा नहीं हुआ। आज भी बूढ़ी मां स्वरूप महिलाएं बेसहारा बनकर भीख मांगने पर मजबूर हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महंगाई चरम पर है। शिक्षा व रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं हैं। समाज में नैतिक पतन व गुण्डागर्दी व्याप्त है। साम्प्रदायिकता व धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है। लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इस तरह शोषण व अन्याय पर आधारित व्यवस्था कायम है और चंद पूंजीपति देश के मालिक बन बैठे हैं। परिणामस्वरुप आम जनता त्राहि त्राहि कर रही है। इसलिए आज समय की मांग है कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस के जीवन संघर्षों से सीख लेकर उनके क्रांतिकारी विचारों के आधार पर लोगों को संगठित करें और जन समस्याओं के खिलाफ संघर्ष तेज करें। कार्यक्रम का संचालन प्रमोद कुमार शुक्ल ने किया। कार्यक्रम को कृष्णा सिंह, नवीन सिंह, दिलीप कुमार खरवार, देवव्रत निषाद, प्रमेन्द्र सिंह (पम्मू), कुंवर आजाद सिंह ने सम्बोधित किए। अंजली सरोज, जिमी गुप्ता ने क्रांतिकारी व देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर इन्दुकुमार शुक्ल, राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, अपूर्व कुमार दुबे, संतोष कुमार प्रजापति, मीता गुप्ता, पूनम प्रजापति, दिवाकर सिंह, जटाशंकर सिंह, नवीन गुप्ता, नवीन सिंह, शिवभवन सिंह, राजबहादुर विश्वकर्मा, राकेश निषाद, विनोद मौर्य, प्रवीण सिंह, सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

पीला नहीं, अब गुलाबी होगा ट्रॉमा सेंटर का परचा

लखनऊ, (संवाददाता)। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) के ट्रॉमा सेंटर में अब पीले के बजाय गुलाबी रंग के

परचे बनेंगे। इसका मकसद दोनों परचों के बीच अंतर करना है। ऐसा देखा गया है कि कई विभाग ओपीडी वाले मरीजों को भी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कर लेते हैं। इससे गंभीर मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता। नई व्यवस्था के बाद इस पर रोक लगेगी। केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में 491 बेड हैं। यहां प्रदेश भर से सड़क दुर्घटना और इमरजेंसी के अन्य गंभीर मरीजों को भर्ती किया जाता है। मरीजों को कैजुएल्टी में प्राथमिक इलाज देकर संबंधित विभाग के वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। विभागों पर मरीजों का दबाव कम रहे, इसलिए कई वार्ड में मरीजों को ओपीडी के माध्यम से भर्ती कर लिया जाता है। ऐसा होने पर ट्रॉमा के वार्ड में बेड भर जाते हैं और गंभीर मरीज भर्ती नहीं हो पाते। इसे देखते हुए केजीएमयू प्रशासन ने ट्रॉमा और ओपीडी के परचों के रंग अलग करने का फैसला लिया है। ऐसा होने पर ओपीडी वाले मरीज दूर से पहचान में आ जाएंगे। इससे गंभीर मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड उपलब्ध रहेंगे। ट्रॉमा सेंटर की कैजुएल्टी से मरीजों को 24 घंटे के भीतर शिफ्ट किया जाना चाहिए। इसके पीछे पहली वजह आने वाले मरीजों को प्राथमिक उपचार के लिए बेड खाली करना और दूसरी मरीज को विशिष्ट उपचार उपलब्ध कराना है। कैजुएल्टी में सिर्फ इमरजेंसी के विशेषज्ञ होते हैं, जबकि अन्य विधाओं के विशेषज्ञ इमरजेंसी के बजाय संबंधित विभाग में बैठते हैं। इसके बावजूद वार्ड के बेड खाली न होने से मरीज और घायलों को कई दिनों तक कैजुएल्टी में रखना पड़ता है। नई व्यवस्था के बाद इस पर रोक लगेगी। प्केजीएमयू की मुख्य ओपीडी और ट्रॉमा सेंटर के परचों के रंग अब अलग होगा। ट्रॉमा सेंटर में अब परचों का रंग गुलाबी होगा। इससे दोनों मरीजों के बीच अंतर हो सकेगा। इस व्यवस्था से ट्रॉमा सेंटर के बेड जरूरतमंद मरीजों के लिए उपलब्ध हो सकेंगे।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।